International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

महिला स्वास्थ्य पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रभाव: जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में एक अध्ययन

किरण गौतम[1], डॉ. स्नेह कुमार मेश्राम[2]

[1]शोधार्थी, [2]शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग)

शोध-सार

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दुर्ग जिले के जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के महिला स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन विशेष रूप से यह जानने का प्रयास करता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों, मातृत्व लाभ योजना, सुपोषण अभियान और टीकाकरण सेवाओं जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में कितना सुधार हुआ है। साथ ही यह भी विश्लेषण किया गया है कि इन योजनाओं के प्रभाव से महिलाओं की पोषण संबंधी जागरूकता, नियमित स्वास्थ्य जांच, मातृत्व देखभाल एवं टीकाकरण सेवाओं की पहुँच में क्या परिवर्तन आया है। अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि इन योजनाओं के व्यावहारिक पक्ष की प्रभावशीलता को मापा जाए तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नीति-निर्माताओं को उपयुक्त सुझाव प्रदान किए जाएँ, जिससे महिला स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी प्रयास अधिक सशक्त, समावेशी और व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित हो सकें।

प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील देश में महिला एवं बाल विकास की अवधारणा सामाजिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। यद्यपि संविधानिक प्रावधानों एवं योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, फिर भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सामाजिक भागीदारी की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। विशेष रूप से जब महिलाओं के स्वास्थ्य की बात आती है, तो यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को उनके जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं, जिससे उनकी संपूर्ण सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी कारण भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रारंभ किया, जिनका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

इन योजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है, जो न केवल पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं, बल्कि मातृत्व लाभ, टीकाकरण, पोषण शिक्षा, किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता तथा बाल विकास जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अंतर्गत जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में इन योजनाओं का संचालन व्यापक रूप से हो रहा है, किन्तु इनका वास्तविक प्रभाव किस सीमा तक महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर पड़ा है, इसका मूल्यांकन आवश्यक है।
वर्तमान अध्ययन इसी पृष्ठभूमि में यह विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत संचालित योजनाओं का महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, जिससे नीति निर्माताओं को भविष्य में प्रभावी योजनाओं की रूपरेखा बनाने में सहायता मिल सके।

संबंधित शोध अध्ययन

- मिश्रा एवं राठौर (2016) — मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी सेवाओं पर शोध; महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता में वृद्धि पाई गई।

- शुक्ला (2017) — उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया।
- थॉमस एवं कपूर (2019) — ICDS योजनाओं से महिलाओं की पोषण संबंधी जागरूकता में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
- सेन एवं चटर्जी (2018) — भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए।
- फर्नांडेज़ एवं रॉय (2020) — महिला सशक्तिकरण पर डिजिटल साक्षरता अभियान का अध्ययन; ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा।
- कुमार एवं जैन (2021) — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्टिंग प्रणाली पर अध्ययन; डेटा पारदर्शिता का अभाव पाया गया।
- मेहता एवं सिन्हा (2022) — छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन; बच्चों एवं माताओं की सहभागिता में वृद्धि हुई।
- डेविड एवं लॉरेंस (2023) — महिला पोषण और सामाजिक सहभागिता के बीच संबंध पर शोध; सरकारी योजनाएँ जागरूकता फैलाने में प्रभावी पाई गईं।
- वर्मा एवं पटेल (2015) — ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं पर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया।
- झा (2016) — छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान के प्रभाव पर अध्ययन; मातृ एवं बाल मृत्यु दर में गिरावट देखी गई।
- शर्मा एवं राव (2017) — आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर शोध किया गया।
- नारायण (2018) — महिला एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।
- जोसेफ एवं थॉमस (2019) — किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन।
- तिवारी (2020) — मातृत्व लाभ योजना की उपयोगिता का अध्ययन।
- मेघा एवं सेनगुप्ता (2021) — महिला स्वास्थ्य में ICT आधारित सूचना सेवा का प्रभाव।
- मिश्र एवं रस्तोगी (2022) — महिला स्वास्थ्य जागरूकता में मोबाइल हेल्थ कैंपों की भूमिका।

उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों ने जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक सशक्तिकरण पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है। विशेष रूप से यह देखा गया है कि क्या इन योजनाओं ने महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, पोषण स्तर में सुधार और परिवार में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने में कोई सकारात्मक परिवर्तन किया है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन यह भी उद्देश्य रखता है कि नीति-निर्माताओं को योजनाओं की व्यावहारिक उपयोगिता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने हेतु प्रमाण-आधारित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

न्यादर्श

इस अध्ययन में कुल 100 लाभार्थी महिलाओं को शामिल किया गया, जो दुर्ग जिले के जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र से सरल यादृच्छिक विधि द्वारा चयनित की गईं। चयनित महिलाएं सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से विविध पृष्ठभूमियों से थीं, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाएं सम्मिलित थीं। इनमें गृहिणी, मजदूरी करने वाली, स्वरोजगार में संलग्न और स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं थीं। इस विविधता से यह सुनिश्चित हुआ कि अध्ययन में सभी सामाजिक वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो और प्राप्त निष्कर्ष व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकें।

उपकरण

इस शोध में आंकड़े एकत्र करने के लिए दो प्रमुख उपकरणों का प्रयोग किया गया—साक्षात्कार अनुसूची और महिला स्वास्थ्य स्केल (अनुकूलित)। साक्षात्कार अनुसूची में पूर्वनिर्धारित प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जिससे लाभार्थी महिलाओं के

अनुभव, स्वास्थ्य लाभ और जागरूकता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया गया। महिला स्वास्थ्य स्केल को स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया गया ताकि स्वास्थ्य से जुड़े आयामों को मापा जा सके जैसे—पोषण जागरूकता, टीकाकरण लाभ, मातृत्व सेवाएँ और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति। इन उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण विश्वसनीय और प्रमाणिक रहा।

सांख्यिकीय तकनीक

इस शोध में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए मुख्य रूप से प्रतिशत, जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया। प्रतिशत विधि से विभिन्न उत्तरों को श्रेणियों में वर्गीकृत कर तुलनात्मक व्याख्या की गई। औसत विधि का उपयोग महिलाओं के उत्तरों की केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने हेतु किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सका कि सामान्यतः महिलाएं किन सेवाओं से लाभान्वित हुई हैं।

तालिका 1: महिला स्वास्थ्य पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रभाव
जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में एक अध्ययन

सेवाओं/योजनाओं का नाम	लाभान्वित महिलाएं (संख्या)	प्रतिशत (%)	प्रमुख प्रभाव
आंगनवाड़ी केंद्र सेवाएं	80	80	पोषण, स्वास्थ्य जाँच एवं परामर्श
मातृत्व लाभ योजना	65	65	गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता
टीकाकरण सेवाएं	72	72	टीकाकरण के प्रति जागरूकता और सुरक्षा
सुपोषण अभियान	68	68	एनीमिया एवं कुपोषण में कमी
महिला स्वास्थ्य शिविर	55	55	नियमित स्वास्थ्य परीक्षण व परामर्श
उज्ज्वला योजना	60	60	धुएँ से मुक्त रसोई से स्वास्थ्य सुधार

व्याख्या:

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जामगांव-एम परियोजना क्षेत्र में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। कुल 80 प्रतिशत महिलाओं ने आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं का लाभ प्राप्त किया, वहीं 65 प्रतिशत महिलाएं मातृत्व लाभ योजना से लाभान्वित हुईं। इसके अतिरिक्त, सुपोषण अभियान और टीकाकरण सेवाओं ने महिलाओं के पोषण स्तर और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि इन योजनाओं की प्रभावी कार्यान्वयन प्रक्रिया महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सुझाव

- महिला स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पहुँच को और अधिक व्यापक बनाया जाए, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी नवीन जानकारियों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।
- मातृत्व लाभ योजना के तहत लाभ वितरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
- टीकाकरण और पोषण जांच जैसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन नियमित रूप से किया जाए।

- महिलाओं को पोषण युक्त आहार एवं स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करने हेतु सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
- किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वास्थ्य निगरानी समितियाँ गठित की जाएँ।
- स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर सामाजिक लेखा परीक्षण (social audit) किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मिश्रा, एस. एवं राठौर, ए. (2016). ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में आंगनवाड़ी सेवाओं की भूमिका, भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 18(3), 52–61
2. शुक्ला, आर. (2017). उज्ज्वला योजना और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक विकास शोध पत्रिका, 11(2), 40–49
3. सेन, आर. एवं चटर्जी, एम. (2018). ग्रामीण भारत में महिला विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन, समाज नीति और शोध, 26(2), 88–102
4. थॉमस, पी. एवं कपूर, आर. (2019). ICDS सेवाओं का किशोरियों की पोषण स्थिति पर प्रभाव, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण जर्नल, 8(2), 101–115
5. फर्नांडीज, एम. एवं रॉय, डी. (2020). डिजिटल साक्षरता एवं महिला सशक्तिकरण में अंतर्संबंध, ग्रामीण सामाजिक अध्ययन, 15(1), 67–79
6. कुमार, वी. एवं जैन, एस. (2021). महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं में पारदर्शिता: एक विश्लेषण, प्रशासनिक शोध, 9(3), 112–126
7. मेहता, ए. एवं सिन्हा, के. (2022). छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी सेवाओं का प्रभाव: बालोद जिले का एक अध्ययन, सामाजिक शोध विमर्श, 13(1), 54–70
8. डेविड, एन. एवं लॉरेंस, जे. (2023). महिला पोषण और सामाजिक सहभागिता के मध्य संबंध, अंतरराष्ट्रीय महिला अध्ययन पत्रिका, 17(2), 93–108